

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 मार्च 2017—चैत्र 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2017

क्र. 8068-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 23 मार्च 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, २०१७**मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा के होते हुए भी, ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, ऊर्जा विभाग की कंपनियों के वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अधीन उधारों को, राज्य की शुद्ध उधार लेने की सामान्य अनुज्ञेय अधिकतम सीमा के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा.”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनी के वित्तीय परिवर्तन हेतु उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) को कार्यान्वित किया है. योजना का उद्देश्य राज्य के डिस्कॉम की परिचालन तथा वित्तीय दक्षता में सुधार करना है. योजना के अन्तर्गत, राज्य से ३० सितम्बर, २०१५ तक के डिस्कॉम ऋणों का अधिग्रहण किए जाने की अपेक्षा की जाती है. राज्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद २९३ (३) के अन्तर्गत ऐसी निधियां उधार लेने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करेगा जिसकी गणना वर्ष २०१६-१७ में राज्य की सामान्य राजकोषीय घाटे की सीमा के अन्तर्गत नहीं की जा सकेगी.

२. राज्य ने इस योजना में सम्मिलित होने का विनिश्चय किया है और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं. भारत सरकार द्वारा राज्य को इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई है.

३. अतएव, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में एक नई उपधारा (३) को जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २१ मार्च, २०१७

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”.

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.